

जबलपुर, बुधवार 24 जून 2026

login : www.haribhoomi.com

सचिव कर रहे मनमानी, आखिर किसकी दम पर चल रहा है भ्रष्टाचार का खेल

सरपंच के हस्ताक्षर के बगैर सचिव ने किया भुगतान, पंचायती राज अधिनियम को बनाया मजाक

हरिभूमि न्यूज़ ►►तामिया, बाबा ठाकुर

जनपद पंचायत तामिया के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मानका देई इन दिनों लगातार विवादों के केंद्र में बनी हुई है। पंचायत सचिव की कार्यप्रणाली को लेकर ग्रामीणों में असंतोष और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सचिव की कथित मनमानी, लापरवाही और वित्तीय अनियमितताओं के कारण पंचायत का विकास प्रभावित हो रहा है। पिछले छह माह से पंचायत में कई कार्यों को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने से लोगों में नाजगामी बढ़ रही है।

जनपद और जिला पंचायत की भूमिका पर सवाल

ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में लगातार शिकायतें और आरोप सामने आने के बावजूद न तो जनपद पंचायत

स्तर पर कोई ठोस हस्तक्षेप दिखाई दे रहा है और न ही जिला पंचायत प्रशासन द्वारा कोई सख्त कदम उठाया गया है। इससे लोगों के बीच यह धारणा मजबूत हो रही है कि शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

श्रीकृष्णा ट्रेडर्स को भुगतान पर उठे सवाल पंचायत दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार निर्माण सामग्री के नाम पर श्रीकृष्णा ट्रेडर्स बिजोरी से रेत खरीदी दशांकर भुगतान किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस भुगतान प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। उनका कहना है कि यदि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।ग्रामीणों के अनुसार भुगतान से संबंधित दस्तावेजों और प्रक्रिया की गहन जांच आवश्यक है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि भुगतान निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुरूप किया गया था या नहीं।



ऑनलाइन भुगतान प्रणाली पर उठे नए सवाल

मामले ने उस समय और गंभीर रूप ले लिया जब ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गईं। पंचायतों में ऑनलाइन भुगतान के दौरान सामान्यतः सरपंच के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आने के बाद ही भुगतान प्रक्रिया पूरी होती है।ऐसे में यदि सरपंच के हस्ताक्षर नहीं हुए और भुगतान फिर भी हो गया, तो ग्रामीण इसे जांच का महत्वपूर्ण विषय बता रहे हैं। पंचायत क्षेत्र में यह चर्चा भी है कि सरपंच के मोबाइल नंबर से संबंधित डुप्लीकेट सिम और डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि इस दिशा में तकनीकी जांच आवश्यक है।

तकनीकी जांच की मांग हुई तेज

ग्रामीणों की मांग है कि यह पता लगाया जाए कि भुगतान किस कंप्यूटर या सिस्टम से किया गया, किस लॉगिन आईडी का उपयोग हुआ और भुगतान प्रक्रिया में किन-किन अधिकारियों अथवा कर्मचारियों की भूमिका रही।उनका कहना है कि यदि साइबर एवं वित्तीय जांच कराई जाए तो भुगतान प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय की जा सकती है।

पंचायती राज व्यवस्था की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल

मानका देई पंचायत का मामला अब केवल एक ग्राम पंचायत तक सीमित नहीं रह गया है। यह पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और निगरानी तंत्र की प्रभावशीलता पर भी बड़ा प्रश्नचिह्न बनकर उभरा है।ग्रामीणों का कहना है कि यदि शिकायतों और आरोपों की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो शासन की योजनाओं तथा पंचायत व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास कमजोर हो सकता है।

निष्पक्ष जांच की उठी मांग

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, जनपद पंचायत और संबंधित विभागों से पूरे मामले की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि भुगतान प्रक्रिया, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, तकनीकी स्वीकृतियों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।अब सबकी निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं। देखना यह होगा कि मानका देई पंचायत में लगाए जा रहे कथित वित्तीय अनियमितताओं और निर्माण कार्यों में गड़बड़ियों के आरोपों की सच्चाई सामने लाने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है। फिलहाल यह मामला पंचायत व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की परीक्षा बन गया है।

हादसे के बाद जागा परिवहन विभाग! 50 स्कूल वाहनों की जांच, 7 जब्त

11 पर चालानी कार्रवाई, लेकिन सवाल बरकरार, स्कूली बच्चों की सुरक्षा में इतनी लापरवाही कैसे?

हरिभूमि न्यूज़ ►►छिंदवाड़ा, मनीष गड़करी

जिले में स्कूल वाहनों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग एक बार फिर चर्चा में है। सोमवार को बिरसा मुंडा क्षेत्र में एक स्कूल वैन के दुर्घटनाग्रस्त होने और चार बच्चों के घायल होने की घटना के बाद मंगलवार को परिवहन विभाग अचानक सक्रिय नजर आया। विभाग के विशेष जांच दल ने शहरी क्षेत्र में संचालित स्कूल वाहनों की सघन जांच करते हुए 50 से अधिक छोटे-बड़े वाहनों की जांच की, 7 वाहनों को जब्त किया और 11 वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 93 बैतुार 800 रुपये का राजस्व वसूला। हालांकि इस कार्रवाई के साथ ही विभाग की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल



भी खड़े हो गए हैं।परिवहन आयुक्त एवं कलेक्टर हरेंद्र नारायण के निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनुराग शुक्ला के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। जांच के दौरान वाहनों के दस्तावेज, फिटनेस, परमिट, चालक के ड्राइविंग लाइसेंस, ओवरलोडिंग तथा अन्य सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की गई।जांच में गंभीर कमियां पाए जाने पर 7 वाहनों को जब्त कर अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन

अधिकारी कार्यालय परिसर में खड़ा कराया गया। इनमें एमपी 28 डीबी 0534, एमपी 28 बीडी 2545, एमपी 20 टी 7756, एमपी 28 जेडएच 2292, एमपी 28 टीए 0845, एमपी 28 बीडी 1428 और एमपी 28 टीए 1545 शामिल हैं। इसके अलावा दस्तावेजों और अन्य नियमों के उल्लंघन के मामलों में 11 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई।अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनुराग शुक्ला ने बताया कि स्कूल वाहन संचालकों और चालकों को मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों का पालन करने की समझाइश भी दी गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बच्चों को हुए नुकसान से अभिभावक है चिंतित

परिवहन विभाग की इस कार्रवाई को लेकर शहर में एक बड़ा सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर ऐसी सचिकता किसी दुर्घटना के बाद ही क्यों दिखाई देती है? यदि सोमवार को बच्चों से जुड़ा हादसा नहीं होता तो क्या यह जांच अभियान चलता/दरअसल, जिले में लंबे समय से ऐसे स्कूल वाहन संचालित होने की शिकायतें मिलती रही हैं जो या तो फिटनेस मानकों पर खरे नहीं उतरते या फिर आवश्यक दस्तावेजों के बिना सड़कों पर दौड़ रहे हैं। कई वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जाता है, जबकि कुछ वाहन तकनीकी रूप से कंडम होने के बावजूद संचालन में बने हुए हैं।परिवहन विभाग का दायित्व केवल दुर्घटना के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि दुर्घटना को रोकना भी है। यदि नियमित रूप से निरीक्षण और निगरानी की व्यवस्था मजबूत हो तो ऐसे कई खोसियों को पहले ही समाप्त किया जा सकता है। लेकिन अवसर देखा गया है कि किसी बड़ी घटना या जनदबाव के बाद ही अभियान चलाए जाते हैं और कुछ दिनों बाद व्यवस्था फिर पुराने दर पर लौट आती है। जिले में परिवहन विभाग के उड़नदस्ते की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यदि नियमित जांच होती रहती तो इतने वाहन एक साथ कमियों के साथ कैसे पकड़े गए? यह स्थिति कहीं न कहीं यह संकेत देती है कि निगरानी व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं।जनता का मानना है कि स्कूल वाहनों की जांच केवल औपचारिकता नहीं बल्कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील विषय है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि जांच अभियान किसी हादसे या कोलैप्स के आदेश का इंतजार किए बिना नियमित रूप से संचालित होें। बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने वाले वाहन सीधे तौर पर अभिभावकों के विश्वास से जुड़े होते हैं। ऐसे में हर वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र, वैध परमिट, प्रशिक्षित चालक और सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।परिवहन विभाग की ताजा कार्रवाई निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, क्योंकि इससे निम्नो का उत्पन्न करने वालों को संदेश गया है। लेकिन यह कार्रवाई तभी सार्थक मानी जाएगी जब इसे एक नियमित अभियान का रूप दिया जाए और जिले की सड़कों पर दौड़ रहे सभी असुरक्षित वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो।फिलहाल विभाग की सक्रियता से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन यह प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है कि क्या छिंदवाड़ा में परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर बार किसी दुर्घटना का इंतजार करना पड़ेगा? जगता अब जवाब और स्थायी समाधान दोनों चाहती है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस बूथ स्तर पर मनाया

छिंदवाड़ा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक एवं माजपा के पितृ पुरुष डॉ.



डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्र प्रथम की भावना, अखंड भारत के संकल्प और जनसेवा के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस अवसर पर बूथ अध्यक्ष राजेश साबले, दिनेश मालवी, गुड्डा सूर्यवंशी, आशेष सोनी, राजीव रॉय,मनीष साहू, हर्ष निर्मलकर, राहुल पाण्डेय, अकिंत सोमकुदर सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम के वार्ड क्रमांक 42 के बूथों पर श्रद्धा एवं समान के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए किए गए संघर्ष तथा उनके बलिदान को याद किया गया।पार्षद संदीप सिंह चौहान ने बताया कि पार्टी संगठन द्वारा वार्ड 42 के बूथों पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके जीवन एवं विचारों पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं को उनके राष्ट्रवादी विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प भी दिलाया गया। पार्षद श्री संदीप सिंह चौहान कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्र प्रथम की भावना, अखंड भारत के संकल्प और जनसेवा के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस अवसर पर बूथ अध्यक्ष राजेश साबले, दिनेश मालवी, गुड्डा सूर्यवंशी, आशेष सोनी, राजीव रॉय,मनीष साहू, हर्ष निर्मलकर, राहुल पाण्डेय, अकिंत सोमकुदर सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

कलेक्टर ने ली समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक, दिए सख्त निर्देश

निगम अभियान चलाकर सड़कों से हटवाए निजी निर्माण सामग्री: कलेक्टर

हरिभूमि न्यूज़ ►►छिंदवाड़ा

कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में समय सीमा प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली । बैठक में समय सीमा के संबंध प्रकरणों की समीक्षा के साथ ही सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई, न्यायालयीन प्रकरणों, वरिष्ठ कार्यालयों एवं विभिन्न आयोगों के संबंध पत्रों की भी विभागवार विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री नारायन ने विभिन्न अंतर्विभागीय एवं समसामयिक विषयों पर भी चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत



श्री अग्रिम कुमार, अपर कलेक्टर श्री धीरेन्द्र सिंह, एसडीएम परासिया श्री शुभम कुमार यादव, एसडीएम छिंदवाड़ा श्री सुधीर जैन, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती ज्योति ठाकुर, श्रीमती अंकिता त्रिपाठी व सुश्री कामनी ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर श्री

राहुल कुमार पटेल, श्री पुष्पेंद्र निगम व श्री आर.के.मेहरा सहित जिला प्रशासन व सभी विभागों के जिला स्तरीय और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। जिला मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य एसडीएम और विभिन्न विभागों के ब्लाॉक स्तरीय

अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल थे। कलेक्टर श्री नारायन ने बताया कि मध्यप्रदेश में भारत सरकार के 'ज्ञान भारत' पांडुलिपि मिशन' के तहत राज्य भर में प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों की खोज और उनके डिजिटलीकरण का व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार जिले में उपलब्ध पांडु लिपियों की खोज और उनके डिजिटाइजेशन का कार्य पूरी जवाबदारी और गंभीरता से किया जाए। इसके लिए उन्होंने विभिन्न विभागों को दायित्व सौंपे हैं। जिला पंचायत कार्यालय से जुड़े समय सीमा के प्रकरण की समीक्षा में पाया गया कि प्रारंभिक जांच में

जिला पेंशन कार्यालय में पदस्थ बाबू द्वारा पेंशन बैंक खाते में भेजने की एवज में पेंशनर से पैसे लेने की शिकायत झूठी और निराधार है। शिकायत में शिकायकर्ता के हस्ताक्षर भी नहीं हैं और संबंधित बाबू को वह कार्य आवंटित भी नहीं है। इस पर कलेक्टर श्री नारायन ने शिकायत कर्ता से सीधे बात कर उनके स्टेटमेंट लेने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री नारायन ने कहा और उनके डिजिटाइजेशन का कार्य पूरी जवाबदारी और गंभीरता से किया जाए। इसके लिए उन्होंने विभिन्न विभागों को दायित्व सौंपे हैं। जिला पंचायत कार्यालय से जुड़े समय सीमा के प्रकरण की समीक्षा में पाया गया कि प्रारंभिक जांच में

निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों की जानकारी प्राप्त की और सभी की प्रगति पर पूरी नजर रखने की शहरी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को दिए, जिससे निर्माण कार्य समय सीमा में एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो सके।

कलेक्टर श्री नारायन ने महाप्रबंधक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में नवीन सदस्य बनाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। सीईओ जनपद पंचायत मोहखेड़ को ग्राम पंचायत सांवरी के सरपंच, सचिव के विरुद्ध हुई शिकायत की स्पष्ट एवं सूक्ष्मता से जांच कराने के लिए निर्देशित किया।

युवक की मौत के बाद भड़के ग्रामवासी, शव को थाने के समक्ष रखकर किया प्रदर्शन

जुन्नारदेव। विकासखंड मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित नवेगांव थाना अंतर्गत जमीनी विवाद के एक मामले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। लगभग एक सप्ताह पूर्व घटित इस मामले को लेकर ग्रामवासी छोटी बोरदेही में पुलिस की कार्रवाई को लेकर असंतुष्ट हैं। युवक की मौत के बाद उसके शव को थाना नवेगांव के समक्ष रखकर ग्राम वासियों ने मंगलवार को जमकर प्रदर्शन किया। आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग को लेकर यह ग्रामवासी इस खबर को लिखे जाने तक प्रदर्शन कर रहे थे। स्थिति बेहद तनाव में जब पहुंच गई थी तब यहां एसडीओपी सुनील बरकडे और तहसीलदार मौका स्थल पर पहुंचकर ग्राम वासियों को समझाने की कोशिश करते देखे गए। मिली जानकारी के अनुसार एक सप्ताह पूर्व थाना नवेगांव के ग्राम छोटी बोरदेही में जमीनी विवाद की लेकर दो पक्ष के बीच विवाद हुई था। जिसमें दबंग पक्ष के द्वारा 42 वर्षीय युवक सुखराम की आज लंबे उपचार के बाद मौत हो गई। ग्राम वासियों के द्वारा इसके शव को लाकर थाना नवेगांव के समक्ष प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर स्थिति बिगड़ती नजर आई ग्राम वासियों ने नवेगांव पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए एसडीओपी सुनील वरकडे और तहसीलदार मौका स्थल पर पहुंच गए हैं, जहां पर वह स्थिति पर नजर रखते हुए प्रदर्शनकारियों को उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दे रहे हैं।

गैस के लिए परासिया के उपभोक्ता हो रहे परेशान

परासिया : - बीते समय गैस की कीमत की किरलत के चलते एक ओर जहां हर आदमी की पेशभियां बढ़ गई थी, वहीं अब स्थिति फिर से खराब हो गई हो , लेकिन परासिया के उपभोक्ताओं को अब भी गैस के लिए खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। पिछले कुछ महीनों में रसीड गैस के लिए जो उहापोह मची थी , हाहाकार मचा था , रसीड गैस के लिए सुबह 5 बजे से गैस सेंटरों में लगी लम्बी कतारों की तस्वीर अखबारों , सोशल मीडिया में छाई हुई थी , तरह - तरह के मीन्स , टूट्स आदि गैस को लेकर बन रही थे , अब उन पर कमी आ गई है । लोगों को रसीड गैस के लिए अब ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ रहा है , लेकिन परासिया के वे उपभोक्ता जिनका कनेक्शन पाटिल गैस एजेंसी से रहा है , उन्हें आज भी गैस के लिए खासा परेशान होना पड़ रहा है । एजेंसी की लापरवाही और कु प्रबंधन का खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगताना पड़ रहा है । परासिया की एजेंसी बंद कर दिए जाने के बाद सभी उपभोक्ताओं को अंबाड़ा और दिघावानी में स्थित एजेंसियों से जोड़ दिया गया । गैस बुकिंग के बाद उपभोक्ता को गैस के लिए अंबाड़ा या दिघावानी जाना पड़ रहा है । हालांकि एजेंसियों को होम डिलीवरी करने के आदेश है , लेकिन इस आदेश का ईमानदारी से पालन नहीं हो रहा है । कांग्रेस नेता वीर बहादुर सिंह ने इस मामले में कलेक्टर को पत्र लिखकर परासिया में ही अस्थाई रूप से सेंटर खोलने और गैस वितरण की व्यवस्था बनाने की मांग रखी है । वीर बहादुर का कहना है , कि शहर के उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग के दौरान कोई समस्या उत्ती है , बिल की कोई समस्या या सिलेंडर लुने आदि के मामले में अंबाड़ा या दीघावानी जाना पड़ता है , जिससे उपभोक्ता का समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है । उन्होंने यह भी कहा , कि गैस एजेंसी खड़ी करने में काफी समय लगेगा , ऐसी स्थिति में उपभोक्ता कब तक परेशानी भोगेगा । उन्होंने शासन से मांग रखी है , कि जल्द ऐसी व्यवस्था बनाई जाए , ताकि परासिया के लोगों को रसीड गैस से सम्बंधित किसी भी मसले का हल परासिया में ही मिल सके । ऐसा नहीं होगा तो आंदोलन किया जाएगा ।

दिल्ली दौरे पर महापौर विक्रम अहके ने केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उड्डे के की मुलाकात

छिंदवाड़ा। जिले के प्रतिभावान जनजातीय युवाओं को खेल के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण पहल की गई है। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम अहके ने भारत सरकार के केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उड्डे जी से प्रत्यक्ष मुलाकात की। इस आत्मीय मुलाकात के दौरान महापौर ने छिंदवाड़ा शहर सहित जिले के वनांचल व ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर विस्तृत चर्चा की और जिले में एक सर्वसुविधायुक्त ‘आदिवासी स्पोर्ट्स एकेडमी’ (जनजातीय खेल आकदमी) स्वीकृत करने की मांग करते हुए उन्हें पत्र सौंपा। महापौर विक्रम अहके ने केंद्रीय मंत्री श्री उड्डे के सीधी चर्चा करते हुए और सीपे गप पत्र में उल्लेख किया कि छिंदवाड़ा जिला एक जनजातीय (आदिवासी) बाहुल्य क्षेत्र है। इस अंचल के आदिवासी युवाओं में खेलों के प्रति स्वाभाविक और बहुमुखी प्रतिभाएं फूट-फूट कर मरी हुई हैं। पारंपरिक खेलों से लेकर आधुनिक खेल दियाओं तक में यहीं के युवाओं का कोशल अद्भूत है, लेकिन उचित मार्गदर्शन, आधुनिक अथोसप्लेस और पेशेवर प्रशिक्षण (कोचिंग) के अभाव में इन प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने का पूरा अवसर नहीं मिल पा रहा है। इन चुनौती हुई खेल प्रतिभाओं को सही समय पर तलाशने और राशनने (बिखरने) की आज महती आवश्यकता है। मुलाकात के दौरान महापौर ने केंद्रीय मंत्री श्री उड्डे के विशेष आग्रह किया कि यदि उनके व्यक्तित्व प्रयासों और केंद्र सरकार के सहयोग से छिंदवाड़ा जिले को ‘आदिवासी स्पोर्ट्स एकेडमी’ की सौगत मिल जाय है, तो यह संपूर्ण महाकोशल और सतपुड़ा अंचल के आदिवासी युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के लिए एक मील का पथर साबित होगा। स्पोर्ट्स एकेडमी खुलने से स्थानीय युवाओं को रहने, खाने, पढ़ाई के साथ-साथ खेलों की आधुनिक विधाओं में अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण निशुल्क मिल सकेगा, जिससे आने वाले समय में जिले के खिलाड़ी देश और दुनिया में छिंरवाड़ा व मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।

वार्ड 20 में बारिश होते ही तारों से निकली आग

छिंदवाड़ा। शहर में काफी दिनों बाद हुई बारिश ने जहां लोगों को राहत दी है। वहीं कुछ स्थानों पर ये आफत बनकर आई है। दरअसल वार्ड क्रमांक 20 माल धक्का के पास बिजली के तार से निकलती आग किसी बड़ी दुर्घटना की न्योता दे रही है। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा जब इसकी शिकायत एसपीईबी की की गई तो उनका कहना था कि उसका काम आज नहीं कल किया जाएगा। विद्युत विभाग की इस तरह की लापरवाही से आग लगने सहित बड़ी दुर्घटना होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मंगलवार सुबह से इस तरह की आग निकल रही है। शिकायत करने के बावजूद भी जिम्मेदार किसी तरह की मरम्मत नहीं करवा रहे हैं।

शहर में सड़क पर मारपीट, रोड पर 15 मिनट चली लड़ाई, एक का सिर फूटा

छिंदवाड़ा। शहर में मंगलवार शाम सड़क पर द्नादन्द देखने को मिला। स्टेटियम के सामने राज टॉकीज जाने वाले तिराह पर आम का ठेला लगाने वाले दो गुटों के बीच मामूली से बात पर शुरू हुई बहस देखते ही देखे मारपीट में बदल गई। इस विवाद में एक युवक का सर भी फूटा, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। करीब 15 मिनट तक रोड पर चले इस घटनाक्रम के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से लोग जमा हुए और दृैफिक जाम रहा लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। शहर में सड़क पर इस तरह की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। जितनाजनक विषय है।

पुलिस के विरुद्ध ओबीसी महासभा में खोला मोर्चा, सौपा ज्ञापन, लापरवाही करने के लगाए आरोप

चौरई। ओबीसी महासभा द्वारा जिले के किसानों एवं अन्य उच्चलत समस्याओं को लेकर मंगलवार को महामहिम राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा । जिसमें पूर्व में हिवरकाता में सौरम मार्गव के द्वारा अपने खाद बीज केन्द्र में ऑसिफ वर्मा के साथ खाद बीज को लेकर मारपीट करने, थाना चौरई के अंतर्गत संदीप वर्मा के विरुद्ध झूठा 376 का प्रकरण दर्ज करने की धमकी देने से उसके द्वारा फांसी लगा लेने, ग्राम कलकौटी निवासी सुचय वर्मा के द्वारा दबंगों की शिकायत थाना चौरई में करने पर मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने, खाद बीज की कीमतों में बेतहाश वृद्धि की वापस लेकर किसानों को राहत दिये जाने, छिंदवाड़ा सहित चौरई की सहकारी समितियों में गन्दम में खाद लेने पर लगाये गये प्रतिबंध को हटकर ई टोकन प्रणाली बंद कर किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध करने, नीट परीक्षा घोटाले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने, चंद, चौरई, बिहुआ सहित संपूर्ण छिंदवाड़ा जिले में रेत के अवैध, परिवहन एवं रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर उनके वाहनों को रोजगार करने, चौरई सहित संपूर्ण ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में अवैध रूप से शराब की बिक्री पर कार्यवाही कर बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग कर इन समस्याओं के त्तरित निराकरण की मांग की है । इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ओबीसी महासभा लोधी विपिन वर्मा अध्यक्ष किसान मोर्चा दिनेश वर्मा अध्यक्ष किसान मोर्चा रंजीत रवि कर रावेध वर्मा विचार वर्मा संजय दिवश्वर्मा सहित ग्रामीण जन एवं ओबीसी महासभा के पदाधिकारी उपस्थित रहे।



खबर संक्षेप
नशामुक्त भारत सप्ताह के अंतर्गत जिलेभर में जनजागरूकता अभियान जारी

हरिभूमि न्यूज सिवनी। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के निदेशानुसार जिले में नशामुक्त भारत सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न जनजागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य आमजन, विशेषकर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना है। इसी क्रम में जिलेभर में प्रचार वाहन के माध्यम से व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। प्रचार वाहन द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भ्रमण कर नशे के दुष्परिणामों, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों तथा नशामुक्त जीवनशैली अपनाने के संबंध में संदेश प्रसारित किया जा रहे हैं। अभियान के तहत नागरिकों को नशे से दूर रहने, परिवार एवं समाज को नशामुक्त बनाने तथा युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न विभागों के समन्वय से शपथ कार्यक्रम, जागरूकता रैलियां, संवाद सत्र एवं अन्य गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है।



विदाई समारोह ग्राम पंचायत सारसडोल के कुछ यादगार पल

हरिभूमि न्यूज सिवनी। ग्राम पंचायत सारसडोल जनपद पंचायत कुर्दू से ग्राम पंचायत धनौरा जनपद पंचायत धनौरा स्थानांतरण होने पर ग्राम पंचायत सारसडोल के ग्रामवासियों, स्नेहजनों और शुभचिंतकों द्वारा मुझे भवभीनी विदाई दी गई। समस्त ग्रामवासियों ने मुझे इस लायक समझा इस हेतु सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

खरीफ सीजन की तैयारियों को लेकर कृषि उत्पादन आयुक्त ने की समीक्षा

हरिभूमि न्यूज सिवनी। कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी) के.सी. गुप्ता ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में खरीफ सीजन की तैयारियों, किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता, मत्स्य उत्पादन, पशुपालन योजनाओं तथा विभागीय प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिला मुख्यालय सिवनी से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अंजली शाह सहित कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सर्पदंश से बचाव और समय पर उपचार के लिए जिले में विशेष जनजागरूकता अभियान जारी

हरिभूमि न्यूज >>>सिवनी। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के निर्देशन में जिले में वर्षाकाल के दौरान संभावित सर्पदंश की घटनाओं की रोकथाम एवं प्रभावी उपचार सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सर्पदंश रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। साथ ही जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जा सके। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि सर्पदंश से होने वाली अधिकांश मौतें घबराहट, अंधविश्वास और उपचार में देरी के कारण होती हैं। इसलिए सर्पदंश होने पर मरीज को शांत एवं स्थिर रहने तथा बिना विलंब न निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पताल पहुंचाएं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को जागरूक

सेंट्रल बैंक मैनेजर के बिगड़े बोल, बीसीयों को बोला कुत्ता

पदभार संभालने के बाद किसी न किसी कारणों से हमेशा रहते है विवादित

हरिभूमि न्यूज छब्बी लाल कमलेशिया लखनादौन/ सिवनी जिले के नेशनल हाईवे 44 पर स्थित ग्राम गणेशगंज में विगत वर्षों से संचालित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक इन दिनों सुर्खियों में है इन्होंने जब से पदभार संभाला है तभी से किसी न किसी कारणों से विवादित चल रहें हैं, कभी बैंक हितग्राही कभी स्टॉप तो कभी बीसी मैनेजर के अभद्रता से व्यथित हैं। एक एहम तथा गरिमामय पद पर पदस्थ बैंक मैनेजर को क्या इस तरह के लहजे सोभा देते हैं।

बैंक बीसीयों का ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष योगदान

बीसी (बिजनेस कॉर्पोरैन्डेंट) जिन्हें बैंक मित्रा के रूप में देखा जाता है। बैंकिंग संस्था अपने हितग्राहियों को बेहतर सेवा देने के लिए चिन्हित स्थानों में बीसीयों को नियुक्त करवाते हैं जो कि ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों के ग्राहकों को स्थानीय स्तर पर विभिन्न सेवा प्रदान करते हैं जिसमें खाता खोलना, नकद जमा करना, नकद निकासी करना, आधार आधारित बैंकिंग सेवाएं, पैसे का ट्रांसफर,बैलेंस की जानकारी प्राप्त करना,सरकारी योजनाओं का भुगतान प्राप्त करना सहित अन्य बैंकिंग महत्वपूर्ण कार्य बीसीयों के द्वारा किया जाता हैं । सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा गणेशगंज के मैनेजर ने जबसे बैंक में अपना पदभार संभाला है तभी से किसी न किसी कारण से वह चर्चाओं में बने हुए हैं। कभी बैंक हितग्राहियों से तू तड़ाक तो कभी बैंक के ही स्टॉप से अनबन और अब एक चौकाने वाली बात सामने आई जब एक बीसी ने केश (नगद) राशि अपने ओडी खाते से निकालने की बात कही तो बीसी सहित स्टॉप पर भडक गए और अभद्रता अशोभनीय अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए बहस बाजी किया यही नहीं बैंक स्टॉप से कहाँ कोई भी बीसी कुत्ता बैंक के अंदर नहीं दिखना चाहिए न इन्हें केश देना है न बैंक के अंदर आने देना है। इन्हें जो करना है ये करलें।

अच्छी खबर: किसानों एवं आवश्यक सेवाओं को राहत: प्लास्टिक कैन में 50 लीटर तक डीजल प्रदाय की अनुमति एक माह के लिए जारी

हरिभूमि न्यूज सिवनी। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित होने के चलते भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मोटर स्प्रिट (पेट्रोल) एवं उच्च वेग डीजल (डीजल) की आपूर्ति के संबंध में अस्थायी विनियमन लागू किया गया है। इसके तहत डीजल का विक्रय केवल वाहनों के टैंक अथवा PEO (Petroleum and Explosives Safety Organization) से अनुमोदित कंटेनरों में ही किया जाना निर्धारित

किया गया है तथा एक ग्राहक/वाहन को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल प्रदाय का प्रावधान किया गया है। किसानों की कृषि आवश्यकताओं, स्वास्थ्य सेवाओं, महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं अन्य अत्यावश्यक सेवाओं की निर्बाध संचालन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश द्वारा जिला कलेक्टरों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। इसी क्रम में कलेक्टर सिवनी द्वारा जिले के किसानों एवं आमजन की

सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए किसान, स्वास्थ्य सेवाओं, महत्वपूर्ण परियोजनाओं तथा अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्लास्टिक कैन में अधिकतम 50 लीटर तक डीजल प्रदाय किए जाने की शिथिलता प्रदान की गई है। इस संबंध में जिले में संचालित सभी पेट्रोल पंप संचालकों एवं तेल कंपनियों के सेल्स अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह व्यवस्था आगामी 30 दिनों तक प्रभावशील रहेगी, जिससे कृषि कार्यो एवं आवश्यक सेवाओं के संचालन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

आगामी मोहर्रम त्योहार के मद्देनजर कोतवाली पुलिस का प्लैग मार्च



संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल एवं वाहन से निकाला प्लैग मार्च, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील

हरिभूमि न्यूज सिवनी। पुलिस अधीक्षक सिवनी कृष्ण लालचंदानी के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सिवनी श्री सचिन परते तथा एसडीओपी बरघाट ललित गटरे के नेतृत्व में आगामी मोहर्रम त्योहार को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु कोतवाली पुलिस द्वारा शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में प्लैग मार्च निकाला गया। त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना, असामाजिक तत्वों में पुलिस की सक्रियता का संदेश देना एवं आमजन में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ करना। प्लैग मार्च रूट-1. पैदल प्लैग मार्च: नगरपालिका चौक से प्रारंभ होकर सुक्रवारी चौक, जैन मंदिर के सामने, निलांजना चौक, छोटी मस्जिद चौक, सोहाने पेट्रोल पंप होते हुए बस स्टैंड से वापस थाना कोतवाली।

जनसुनवाई में पहुंचा वैनगंगा में बेतरतीब उत्खनन का मुद्दा कलेक्टर ने सिंचाई विभाग से शीघ्र कार्रवाई के दिए निर्देश

हरिभूमि न्यूज >>>सिवनी।

मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में छपारा में वैनगंगा नदी में बेतरतीब तरीके से किए जा रहे उत्खनन का मामला कलेक्टर के सामने उठाया गया। जिसके बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र करने के निर्देश दिए गए। शिकायतकर्ताओं ने अपेक्षा जताई है कि जिले की संवेदनशील कलेक्टर इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करेंगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगी जिससे भविष्य में जिले के पर्यावरण से खिलवाड़ करने की कोशिश न हो।

क्या है मामला- छपारा तहसील मुख्यालय के पास बहने वाली और सजय सरोवर बांध की डूब क्षेत्र में आने वाली वैनगंगा नदी में मई महीने में पीएन नाग, कार्यपालन यंत्री ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुए नगरपरिषद छपारा को सिल्ट निकालने की अनुमति दे दी। पीएन नाग ने अपने अनुमति पत्र में गौण खनिज अधिनियम का हवाला देते हुए अनुमति दी है जबकि डूब क्षेत्र की भूमि आर्द्र भूमि के तहत आती है। इसके अलावा सिल्ट निकालने के आदेश का फैसला शासन स्तर से होता है और सभी नदियों और बांधों के लिए

छत्रपति शाहू महाराज की जयंती एवं रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पखवाड़ा पर 26 को विचार संगोष्ठी का आयोजन

हरिभूमि न्यूज सिवनी। बहुजन समाज पार्टी विधानसभा क्षेत्र बरघाट/सिवनी के तत्वावधान में 26 जून 026 को डडेरिया समाज मंगल भवन गंगा नगर सिवनी में दोपहर 12 बजे से वीरगंगा रानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस पखम आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती के मौके पर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। ज्ञात हो गोंडवाना साम्राज्य की साहसी महारानी दुर्गावती जी द्वारा मुगल सेना से लड़ते हुए 24 जून 1664 को अपनी आनखों पखम शान के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था तथा छत्रपति शाहू जी महाराज का जन्म 26 जून 1874 को कुर्मी समाज में हुआ था छत्रपति शाहू जी महाराज जब कोल्हापुर रियासत के राजा हुए तो उनके द्वारा 26 जूनलाई 1902 की राज्य के वंचित वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की शुरुवात की गई।

हिंदुओं के लिए समर्पित रहेगा संगठन का आठवां स्थापना दिवस: रोहित सक्सेना

अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल का आठवां स्थापना दिवस इस वर्ष पूरे जिले में मत्स्य एवं व्यापक रूप से मनाया जाएगा। हरिभूमि न्यूज >>>सिवनी।

महाकौशल प्रांत के सिवनी जिले के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रोहित सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि संगठन का स्थापना दिवस हिंदू समाज की एकता, सांस्कृतिक चेतना, सेवा, सुरक्षा एवं राष्ट्र समर्पण की भावना को समर्पित



रहेगा। उन्होंने बताया कि सिवनी जिले के विभिन्न नगरों, मंडलों एवं ग्राम इकाइयों में कुल 31 स्थानों पर स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें कई स्थानों पर ध्वजारोहण, संगठन परिचय, हिंदू जागरण गोष्ठियां, कार्यकर्ता सम्मान, सेवा गतिविधियां तथा समाज के

विभिन्न वर्गों के साथ संवाद जैसे कार्यक्रम संपन्न होंगे। रोहित सक्सेना ने बताया कि जिले में नए हनुमान चालीसा केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र से जुड़े गणमान्य नागरिक तथा बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग उपस्थित रहेंगे।



मुस्लिम विकास परिषद ने पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी का किया सम्मान

मध्यप्रदेश मुस्लिम विकास परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने आज पुलिस अधीक्षक सिवनी कृष्ण लालचंदानी से सौजन्य भेंट कर उन्हें जलसेवा, समाजसेवा, उत्कृष्ट कानून-व्यवस्था तथा जिले में सभी धर्मों एवं समुदायों के बीच आपसी प्रेम, शांति एवं सौहार्द का वातावरण बनाए रखने में दिए जा रहे उत्क्रेखनीय योगदान के लिए पुष्पहार एवं सम्मान-पत्र भेंट कर सम्मानित किया। परिषद के सरपरस्त नवाब दीवान शाद अली एवं प्रदेश महामंत्री शोएब राजा के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष साजिद खान, उपाध्यक्ष असलम मिर्जा तथा कोषाध्यक्ष रहैम खान शामिल रहे। इस अवसर पर परिषद पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी के नेतृत्व में जिले में बेहतर कानून-व्यवस्था स्थापित करने, सामाजिक समरसता को मजबूत करने तथा सभी वर्गों में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण निर्मित करने के प्रयासों की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया।

सिवनी जम्बो सीताफल को मिला जीआई टैग

किसानों को मिलेगा बेहतर मूल्य और वैश्विक पहचान

हरिभूमि न्यूज >>>सिवनी।

सिवनी जिले के लिए गौरव और हर्ष का विषय है कि जिले के प्रसिद्ध सिवनी जम्बो सीताफल को भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि जिले की विशिष्ट कृषि पहचान तथा किसानों की मेहनत को राष्ट्रीय स्तर पर मिली महत्वपूर्ण मान्यता है। जीआई टैग मिलने से सिवनी जम्बो सीताफल को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान मिलेगी तथा किसानों को अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा। सिवनी जम्बो सीताफल अपने बड़े आकार, उत्कृष्ट गुणवत्ता और प्राकृतिक रूप से विकसित होने वाले विशिष्ट मोठे स्वाद के लिए देशभर में प्रसिद्ध है। इस सीताफल का औसत वजन 200 से 650 ग्राम प्रति फल होता है, जबकि भूतबंधानी क्षेत्र में उत्पादित कई फल 800 ग्राम से लेकर एक किलोग्राम तक वजन के पाए जाते हैं। जीआई टैग मिलने से इस उत्पाद की विशिष्ट पहचान सुरक्षित रहेगी तथा इसके नाम के दुरुपयोग पर रोक लगेगी। सहायक संचालक उद्यानिकी सिवनी डॉ. आशा उपवंशी-वासेवार ने बताया कि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा कलेक्टर सिवनी एवं आयुक्त उद्यानिकी के मार्गदर्शन में वर्ष 2023 में भूतबंधानी सीताफल क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के माध्यम से जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप सिवनी जम्बो सीताफल को यह



महत्वपूर्ण मान्यता प्राप्त हुई है। जीआई टैग मिलने से जिले के हजारों सीताफल उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। अब सिवनी में उत्पादित सीताफल को उसकी विशिष्ट पहचान के साथ बाजार में प्रस्तुत किया जा सकेगा और अन्य क्षेत्रों के उत्पादक इसके नाम का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इससे उत्पाद की मांग और मूल्य दोनों में वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही सीताफल उत्पादन, क्षेत्र विस्तार और प्रसंस्करण गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

वर्तमान में सिवनी जिले में लगभग 695 हेक्टेयर क्षेत्र में सीताफल की खेती की जा रही है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 6090 मीट्रिक टन उत्पादन प्राप्त होता है। जिले का सीताफल देश के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, नागपुर, रायपुर, वाराणसी और अन्य बाजारों में विशेष मांग रखता है। सीताफल का उपयोग प्रसंस्करण कर पल्प बनाने में भी किया जाता है, जिससे सीताफल आइसक्रीम, रबड़ी, बासुंदी, लस्सी, शेक तथा विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त सीताफल के पत्तों एवं छिलकों का उपयोग जैविक खाद तथा औषधीय उत्पादों के निर्माण में भी किया जाता है। जिले में सीताफल उत्पादकों को संगठित कर दो एफपीओ का गठन किया गया है तथा तीन सीताफल पल्प प्रसंस्करण इकाइयों भी स्थापित की गई हैं। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना, जिला उद्यानिकी अधिकारी डॉ. आशा उपवंशी-वासेवार तथा जिला प्रशासन एवं उद्यानिकी विभाग ने इस उपलब्धि पर जिले के किसानों, उद्यानिकी विशेषज्ञों एवं सभी संबंधित हितधारकों को बधाई दी है। कलेक्टर ने विश्वास व्यक्त किया कि जीआई टैग के माध्यम से सिवनी जम्बो सीताफल को देश और विदेश के बाजारों में नई पहचान मिलेगी तथा इससे जिले के किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। यह उपलब्धि सिवनी की कृषि विरासत को सशक्त बनाने और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।



